भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4845

(जिसका उत्तर सोमवार, 23 मार्च, 2026 /02 चैत्र, 1948 (शक) को दिया जाना है)

राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन

4845. श्री बी.वाई. राघवेन्द्रः

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के शुरुआत से अब तक इसके अंतर्गत परियोजनाओं की पहचान करके अवसंरचना विकास को आगे बढ़ाने और राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के माध्यम से निवेश जुटाने में क्या प्रगति हुई है;

(ख) जुटाए गए निवेश, शुरू की गई परियोजना का ब्यौरा क्या है और इन पहलों के अंतर्गत निजी क्षेत्र की भागीदारी की सीमा का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) अवसंरचना विकास और आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए केन्द्र सरकार के बढ़े हुए पूंजीगत व्यय ने इन पहलों में किस प्रकार सहायता की है; और

(घ) अवसंरचना के वित्तपोषण को और अधिक व्यापक बनाने और अवसंरचना क्षेत्रों में दीर्घकालिक निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से संस्थागत और वित्तीय नवाचार शुरू किए गए हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री

(श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) को अवसंरचना परियोजनाओं और वित्तपोषण आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए एक संपूर्ण सरकारी पहल के रूप में शुरू किया गया था। एनआईपी एक गतिशील पाइपलाइन थी जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों/राज्य सरकारों द्वारा आवश्यकतानुसार परियोजनाओं और उनके विवरणों को जोड़ा गया, संशोधित किया गया और हटा दिया गया। वर्ष 2019-20 से, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों ने विभिन्न क्षेत्रों में 14,674 एनआईपी परियोजनाएं शुरू की हैं। इनमें से, सड़क क्षेत्र में 8,131 परियोजनाएं हैं, जबकि शहरी विकास (1,531 परियोजनाएं) और रेलवे (846 परियोजनाएं) जैसे क्षेत्र भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, शेष परियोजनाएं अन्य अवसंरचना क्षेत्रों में फैली हुई हैं।

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन 1.0 (एनएमपी 1.0) में चार साल की अवधि (2021- 22 से 2024-25) के दौरान ₹6 लाख करोड़ की मुद्रीकरण क्षमता वाली आस्तियां शामिल थीं, जिसकी तुलना में लगभग ₹5.3 लाख करोड़ प्राप्त किए गए थे।

एनएमपी 1.0 के तहत प्रमुख क्षेत्रों की उपलब्धियों को नीचे दी गई तालिका में प्रस्तुत किया गया है

क्षेत्र	**मुद्रीकृत राशि (₹ लाख करोड़ लगभग)**
सड़क	1.1
रेलवे	0.3
विद्युत	0.5
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	0.4
कोयला	2
शिपिंग	0.2
खान	0.4
शहरी	0.1

इन पहलों के अंतर्गत परियोजना विशिष्ट पहलुओं जैसे कार्यक्षेत्र, निजी निवेश आदि का ब्यौरा संबंधित परियोजना प्रायोजक प्राधिकरणों द्वारा रखा जाता है।

(ग) और (घ): पिछले कुछ वर्षों में, सरकार ने अवसंरचना क्षेत्र में निवेश में काफी वृद्धि की है, जिससे निजी निवेश में भीड़ लगने की उम्मीद है। यह बढ़ा हुआ सार्वजनिक निवेश अवसंरचना के विकास के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर उपर्युक्त पहलों का पूरक है। निजी क्षेत्र की भागीदारी को आकर्षित करने के लिए कई उपाय शुरू किए गए हैं जिनमें व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) के साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) का समर्थन करना, अवसंरचना निवेश न्यास (इनविट), रियल एस्टेट निवेश न्यास (आरईआईटी), और अवसंरचना ऋण निधि (आईडीएफ) जैसे नवीन वित्तपोषण साधनों के लिए सुधार करना और निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए आस्ति पुनर्चक्रण मॉडल का उपयोग करना शामिल है। अवसंरचना क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (एनआईआईएफ) और राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्तपोषण बैंक (एनएबीएफआईडी) जैसी संस्थाएं भी स्थापित की गई हैं।

****